नईदुनिया

संपादकीय

अवैध अतिक्रमण और अपराधः प्रशासनिक निष्क्रियता का दुष्चक्र

देश में अवैध अतिक्रमण की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। आमतौर पर इसे केवल 'भूमि का अवैध कब्जा' या 'शहरी भूखंडों पर अवैध निर्माण' के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन हाल के घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि अवैध अतिक्रमण केवल भूमि या संपत्ति का मुद्दा नहीं है, बल्कि अपराध और सामाजिक असुरक्षा का भी केंद्र बन गया है।

दिल्ली के पास एक कॉलोनी में हाल ही में हुई घटना इस दुष्चक्र का उदाहरण है। एक बच्ची द्वारा किसी परिजन पर रंग फेंकने की मामूली घटना के बाद रंग का छींटा एक मुस्लिम महिला पर पड़ गया। इसके बाद उसके परिवार के सदस्यों ने प्रतिक्रिया स्वरूप पीड़ित परिवार पर हमला कर दिया, जिससे 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई और पूरे परिवार को गंभीर चोटें आईं। घर में तोड़फोड़ की गई और स्थिति इतनी बिगड़ी कि पुलिस को बीच में आकर प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी।

यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। जब अपराध हो चुका, तब नगर निगम प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और घर को अवैध अतिक्रमण घोषित करके बुलडोज़र से गिरा दिया। यह घटनाक्रम बताता है कि हमारे शहरी प्रशासन का दृष्टिकोण केवल 'दुर्घटना के बाद कार्रवाई' तक सीमित है। अपराध रोकने के बजाय, अपराध के बाद की कार्रवाई अधिक दिखाई देती है।

अपराध और अतिक्रमण का रिश्ता भी गहरा है। जब किसी परिवार या समूह को यह विश्वास हो जाता है कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है और प्रशासन उनकी गतिविधियों पर निगरानी नहीं रखता, तो छोटे विवाद बड़ी हिंसा में बदल जाते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में बच्ची द्वारा रंग फेंकने जैसी मामूली घटना ने रक्तरंजित संघर्ष का रूप ले लिया। अतिक्रमण केवल भूमि का कब्जा नहीं होता; यह अक्सर सामाजिक संरचना में असमानता, राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक लापरवाही के कारण बढ़ता है। ऐसे स्थानों पर रहने वाले लोग अक्सर कानून से परे महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास किसी न किसी का संरक्षण है और यही संवेदनशील स्थिति कई बार अपराध को जन्म देती है।

नगर निगम और प्रशासनिक निष्क्रियता का पहलू भी इस समस्या को गहरा करता है। दिल्ली में जैसे ही बुलडोज़र गिरता है, वह कार्रवाई केवल घटना के बाद की होती है। प्रश्न यह उठता है कि क्या नगर निगम या स्थानीय प्रशासन ने कभी इन अतिक्रमणों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

अक्सर पार्षद, विधायक और स्थानीय अधिकारी अतिक्रमण के निर्माण के समय चुप रहते हैं या इसे प्रोत्साहित करते हैं। राजनीतिक संरक्षण से अतिक्रमणकर्ता हतोत्साहित नहीं होते, बल्कि उनका हौसला और बढ़ जाता है। केवल प्राथमिकी दर्ज कर बुलडोज़र गिराना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। यह कार्रवाई केवल 'सज़ा के बाद की राहत' जैसी प्रतीत होती है।

इस निष्क्रियता के कारण अपराधियों को यह विश्वास हो जाता है कि वे किसी भी समय जमीन पर कब्जा कर सकते हैं और प्रशासन केवल बाद में हस्तक्षेप करेगा। यह दुष्चक्र केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। अपराध को रोकने के लिए अतिक्रमण पर पहले कार्रवाई आवश्यक है। सही दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि प्रशासन अपराध होने से पहले ही सक्रिय कदम उठाए। इसके लिए नगर निगम, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक विभागों के बीच संयुक्त निगरानी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, ताकि अतिक्रमण शुरू होने से पहले ही चेतावनी और रोकथाम की कार्रवाई हो सके।

आजकल

परीक्षा तनाव : निजी संस्थानों की भूमिका और काउंसलिंग की आवश्यकता

भारत में बोर्ड परीक्षाओं का समय आते ही घर-घर में तनाव का माहौल बन जाता है। छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, वहीं अभिभावक बच्चों के परिणाम को लेकर असमंजस और दबाव महसूस करते हैं। विशेष रूप से सीबीएसई और अन्य बोर्ड परीक्षाओं के दौरान यह तनाव कई गुना बढ़ जाता है। यह स्थिति केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। कई मामलों में परीक्षा और परिणाम के दबाव के कारण छात्र अवसाद में चले जाते हैं और कुछ दुखद घटनाएँ भी सामने आती हैं। इस पूरे वातावरण का लाभ निजी कोचिंग संस्थान और शैक्षणिक मार्गदर्शन देने वाले निजी संगठन उठाते हैं। वे परीक्षा के डर और प्रतिस्पर्धा को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, जिससे अभिभावक और छात्र महंगे पाठ्यक्रम, कोचिंग और परामर्श सेवाओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यह स्थिति एक प्रकार का शैक्षणिक बाजार बना देती है, जहाँ चिंता और असुरक्षा को भी अवसर के रूप में देखा जाता है।

वास्तव में परीक्षा जीवन का केवल एक चरण है, लेकिन हमारे समाज में इसे जीवन-मरण का प्रश्न बना दिया गया है। परिणामस्वरूप बच्चों पर अत्यधिक अपेक्षाओं का बोझ पड़ता है। अभिभावकों की अनजाने में बढ़ती अपेक्षाएँ, समाज में अंकों पर आधारित सफलता की परिभाषा और सीमित करियर विकल्पों की समझ इस तनाव को और बढ़ा देती है।

ऐसी स्थिति में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्कूलों और जिला स्तर पर निःशुल्क परामर्श केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, जहाँ प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक और करियर विशेषज्ञ बच्चों तथा अभिभावकों को सही मार्गदर्शन दे सकें। इन केंद्रों के माध्यम से छात्रों को यह समझाया जा सकता है कि परीक्षा केवल ज्ञान का आकलन है, जीवन की अंतिम कसौटी नहीं है। साथ ही करियर के विविध विकल्पों की जानकारी देकर अनावश्यक दबाव को कम किया जा सकता है।

रूस-चीन की छाया : ईरान युद्ध में वैश्विक शतरंज का खेल

डॉ. शैलेश शुक्ला

रूस और चीन का संयुक्त रुख इस संघर्ष को लंबा खींचने वाला साबित हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका को घेरने की रणनीति दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों देशों की अपनी सीमाएं भी स्पष्ट हैं-रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और चीन आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस संघर्ष से जहां बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की संभावना मजबूत हो सकती है, वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान और परमाणु टकराव का जोखिम भी बढ़ सकता है। ऐसे में यह संकट स्पष्ट रूप से कूटनीति और संवाद की आवश्यकता को रेखांकित करता है, अन्यथा रक्तरंजित रणभूमि वैश्विक आपदा का रूप ले सकती है।

ईरान-अमेरिका-इज़राइल युद्ध का नौवां दिन न केवल मध्य पूर्व को रक्तरंजित रणक्षेत्र में बदल रहा है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को पुनर्परिभाषित करने वाली भू-राजनीतिक शतरंज की नई चालें भी सामने ला रहा है, जहां रूस और चीन की भूमिका सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी हुई है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस संघर्ष में, जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं, तेल भंडार, शोधन संयंत्र और सैन्य ठिकानों पर 3,000 से अधिक हवाई हमले किए हैं, वहीं रूस और चीन ने सतही कूटनीतिक निंदा से आगे बढ़कर हथियार आपूर्ति, गुप्तचर सहयोग और आर्थिक सहायता के माध्यम से ईरान को मजबूती प्रदान की है, हालांकि दोनों ही महाशक्तियां प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या को 'अंतरराष्ट्रीय कानून का शर्मनाक उल्लंघन' करार दिया, जबकि चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका-इज़राइल गठबंधन को 'क्षेत्रीय संप्रभुता का घोर उल्लंघन' बताया। यह संपादकीय रूस और चीन की बहुआयामी भूमिका का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें उनकी रणनीतिक प्रेरणाएं, व्यावहारिक सहायता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रुख, साथ ही इस युद्ध से उन्हें होने वाले संभावित फायदे और नुकसान का विस्तृत मूल्यांकन शामिल है। वास्तव में, यह युद्ध रूस-चीन गठजोड़ के लिए अवसर और संकट दोनों का रूप ले चुका है, जो वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने या तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेलने का निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।

रूस की भूमिका इस युद्ध में सबसे जटिल और बहुआयामी रही है, जो उसके यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न रणनीतिक बाध्यताओं, ऊर्जा हितों और वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित है। सबसे पहले, कूटनीतिक मोर्चे पर रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका-इज़राइल हमलों की तीखी निंदा की, जहां रूसी राजदूत वासिली नेबेन्ज़्या ने इसे 'नई साम्राज्यवादी आक्रामकता' का नाम दिया और चेतावनी दी कि इससे मध्य पूर्व में 'पूर्ण विखंडन' हो सकता है।

व्यावहारिक सहायता के स्तर पर रूस ने ईरान को उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति तेज कर दी, जो ईरानी जवाबी हमलों में स्पष्ट दिखाई दी-जैसे जॉर्डन पर 100 से अधिक मिसाइल और मानवरहित विमानों के हमलों में केवल 14 को रोका जा सका, जिससे अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली को गंभीर क्षति पहुंची। गुप्तचर और सैन्य सहयोग में भी वृद्धि हुई; विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार रूस ईरान को उपग्रह आधारित मार्गदर्शन और सूचनात्मक सहयोग दे रहा है, जिसका उपयोग हाइफा के शोधन संयंत्र, दुबई के समुद्री क्षेत्र और बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर सटीक हमलों में हुआ। इसके अतिरिक्त रूस ने ईरान को उन्नत लड़ाकू विमान, समुद्र से प्रक्षेपित होने वाली क्रूज़ मिसाइलें और मानवरहित विमानों के उत्पादन की तकनीक की आपूर्ति तेज कर दी, हालांकि रूस-ईरान 2025 के रणनीतिक साझेदारी समझौते में प्रत्यक्ष युद्ध में प्रवेश का कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है। पुतिन सरकार यूक्रेन में भारी जनहानि और आर्थिक प्रतिबंधों के बोझ से पहले ही दबाव में है, इसलिए मॉस्को ने 'गैर-शत्रुतापूर्ण सहायता' की नीति अपनाई है, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य में रूस-ईरान-चीन के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी शामिल रहे हैं। रूस ने ईरान को परमाणु ईंधन संवर्धन तकनीक में भी सहयोग दिया है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इसे शांतिपूर्ण सहयोग बताया है।

रूस को इस युद्ध से होने वाले संभावित फायदे अनेक और रणनीतिक हैं। पहला, वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल से प्रत्यक्ष लाभ; होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने की आशंका से तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं, जिससे रूस को आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारी अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है। दूसरा, अमेरिका का सैन्य ध्यान मध्य पूर्व में बंटने से यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर दबाव कम हुआ है। तीसरा, वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था को बढ़ावा; उभरते आर्थिक समूहों के विस्तार के साथ डॉलर आधारित व्यापार व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश तेज हुई है। चौथा, हथियार निर्यात में वृद्धि की संभावना।

लेकिन इसके नुकसान भी कम गंभीर नहीं हैं। लंबे युद्ध से रूस के ऊर्जा व्यापार और आर्थिक हितों को झटका लग सकता है, जबकि नए प्रतिबंध उसकी रक्षा उद्योग प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण संसाधन पहले ही सीमित हैं और नया मोर्चा आर्थिक दबाव को और बढ़ा सकता है। सबसे बड़ा खतरा परमाणु टकराव का है, जो विश्व स्तर पर विनाशकारी परिणाम ला सकता है। आंतरिक स्तर पर भी युद्ध से जुड़े निर्णयों को लेकर असंतोष बढ़ने की आशंका है।

चीन की भूमिका अधिक परिपक्व, आर्थिक रूप से प्रेरित और दीर्घकालिक रणनीति पर आधारित दिखाई देती है, जो उसके वैश्विक व्यापार मार्गों, ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने की नीति से जुड़ी हुई है। कूटनीतिक स्तर पर चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका को वैश्विक अस्थिरता का प्रमुख कारण बताया और कई देशों के नेताओं से संवाद स्थापित कर मध्यस्थता का प्रयास किया। आर्थिक स्तर पर चीन ने ईरान को आपात ऋण सहायता दी, बंदरगाह परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया और क्षेत्रीय व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने की कोशिश की। सैन्य सहयोग अपेक्षाकृत सीमित और अप्रत्यक्ष रहा, लेकिन तकनीकी सहायता और गुप्तचर साझेदारी के संकेत मिलते रहे हैं।

चीन को भी इस संघर्ष से कुछ रणनीतिक लाभ मिल सकते हैं। अमेरिका का ध्यान मध्य पूर्व की ओर केंद्रित होने से पूर्वी एशिया में दबाव कम हो सकता है। ऊर्जा आपूर्ति के नए विकल्पों और क्षेत्रीय व्यापार में अवसर भी बढ़ सकते हैं। साथ ही विकासशील देशों के बीच चीन की कूटनीतिक साख मजबूत होने की संभावना है।

हालांकि इसके जोखिम भी बड़े हैं। क्षेत्र में चीन के भारी निवेश और व्यापारिक परियोजनाएं युद्ध से प्रभावित हो सकती हैं। ऊर्जा संकट का असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और वैश्विक स्तर पर नए प्रतिबंधों का खतरा भी बना रह सकता है। यदि युद्ध का विस्तार हुआ तो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भी तनाव बढ़ सकता है।

रूस और चीन का संयुक्त रुख इस संघर्ष को लंबा खींचने वाला साबित हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका को घेरने की रणनीति दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों देशों की अपनी सीमाएं भी स्पष्ट हैं-रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और चीन आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस संघर्ष से जहां बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की संभावना मजबूत हो सकती है, वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान और परमाणु टकराव का जोखिम भी बढ़ सकता है। ऐसे में यह संकट स्पष्ट रूप से कूटनीति और संवाद की आवश्यकता को रेखांकित करता है, अन्यथा रक्तरंजित रणभूमि वैश्विक आपदा का रूप ले सकती है।

क्या भारत-नेपाल संबंधों में आएगा ऐतिहासिक बदलाव

नेपाल की राजनीति में नया मोड़

नेपाल की राजनीति इन दिनों एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। हाल के चुनावों में मात्र चार वर्ष पुरानी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने जिस तरह अप्रत्याशित सफलता हासिल की है, उसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस चुनाव में पार्टी के नेता बालेन शाह ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लगभग पचास हजार से अधिक मतों से पराजित कर राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। नेपाल में यह परिणाम केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक राजनीति के खिलाफ जनता के असंतोष और बदलाव की इच्छा का प्रतीक माना जा रहा है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इस राजनीतिक परिवर्तन का असर भारत-नेपाल संबंधों पर भी पड़ेगा।

नेपाल में लंबे समय से कुछ प्रमुख दलों का राजनीतिक वर्चस्व रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां शामिल रही हैं। दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद इन दलों पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और विकास की धीमी गति के आरोप लगते रहे हैं। इसी असंतोष ने नए राजनीतिक विकल्पों के लिए रास्ता तैयार किया। युवा मतदाताओं, शहरी वर्ग और शिक्षित नागरिकों ने पारंपरिक दलों के बजाय नए नेतृत्व को मौका देने का निर्णय लिया। यही कारण है कि अपेक्षाकृत नई और वैकल्पिक राजनीति का दावा करने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी तेजी से लोकप्रिय हुई। यह परिणाम नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पहली बार इतनी नई पार्टी ने स्थापित नेताओं को चुनौती देते हुए निर्णायक बढ़त बनाई है।

नेपाल में इस बदलाव के केंद्र में जिस व्यक्ति का नाम सबसे अधिक चर्चा में है, वह हैं बालेन शाह। वे मूलतः एक इंजीनियर और रैपर के रूप में भी पहचान रखते रहे हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद उन्होंने भ्रष्टाचार विरोध, पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया। काठमांडू के मेयर के रूप में उनकी लोकप्रियता पहले ही काफी बढ़ चुकी थी। युवा पीढ़ी उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखती है जो पारंपरिक राजनीतिक ढांचे से बाहर का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, बालेन शाह के कुछ बयान विवादास्पद भी रहे हैं। उन्होंने पहले नेपाल की कुछ सरकारों को 'भारत की गुलाम सरकार' कहकर आलोचना की थी। इस बयान ने भारत-नेपाल संबंधों पर बहस को और तेज कर दिया है।

भारत और नेपाल के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक स्तर पर भी बेहद गहरे हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, जिसके कारण लोगों का आवागमन सहज रूप से होता रहा है। नेपाल के लाखों नागरिक भारत में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या व्यवसाय करते हैं। कई अनुमान बताते हैं कि नेपाल के लगभग 70 से 80 प्रतिशत परिवारों का किसी न किसी रूप में भारत से संबंध है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 'रोटी-बेटी का रिश्ता' कहा जाने वाला सामाजिक संबंध भी बहुत मजबूत है। विवाह, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान ने दोनों समाजों को गहराई से जोड़ा है। नेपाल के कई प्रमुख नेता भी भारत में पढ़ाई कर चुके हैं या उनका भारत से गहरा संपर्क रहा है। इसलिए दोनों देशों के रिश्तों में केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि लोगों के बीच विश्वास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यदि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाल की सत्ता में आती है, तो सबसे बड़ा प्रश्न उसकी विदेश नीति को लेकर होगा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी बयान और वास्तविक शासन में काफी अंतर होता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत पर निर्भर है। व्यापार, ऊर्जा, परिवहन और रोज़गार के कई क्षेत्रों में भारत नेपाल का सबसे बड़ा साझेदार है। ऐसे में कोई भी सरकार भारत से पूरी तरह दूरी बनाने का जोखिम नहीं उठा सकती।

दूसरी ओर नेपाल में लंबे समय से संतुलित विदेश नीति की मांग भी उठती रही है। कई नेता चाहते हैं कि नेपाल भारत और चीन दोनों के साथ संतुलित संबंध रखे, ताकि राष्ट्रीय हितों को बेहतर तरीके से साधा जा सके। पिछले एक दशक में नेपाल की राजनीति में चीन का प्रभाव भी बढ़ा है। चीन ने नेपाल में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, निवेश और कूटनीतिक सक्रियता के माध्यम से अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश की है। इसी कारण नेपाल की नई राजनीतिक शक्तियां अक्सर यह कहती रही हैं कि देश को अपनी विदेश नीति में अधिक स्वतंत्रता और संतुलन रखना चाहिए। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से भारत का महत्व नेपाल के लिए हमेशा बना रहेगा। इसलिए नेपाल चाहे जितनी भी नई दिशा में आगे बढ़े, भारत-नेपाल संबंध पूरी तरह बदलना आसान नहीं होगा।

नेपाल की राजनीति में यह परिवर्तन केवल एक सरकार के बदलने का मामला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की परिपक्वता और जनता की बदलती अपेक्षाओं का संकेत भी है। युवा मतदाता अब पारदर्शिता, विकास और जवाबदेही की राजनीति चाहते हैं। सामाजिक माध्यमों और नई पीढ़ी की सक्रियता ने भी इस परिवर्तन को गति दी है। यदि नई राजनीतिक ताकतें अपने वादों पर खरा उतरती हैं, तो नेपाल में प्रशासनिक सुधार और विकास की नई दिशा देखने को मिल सकती है। भारत और नेपाल के रिश्ते कई ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव से गुजर चुके हैं, लेकिन हर बार दोनों देशों ने संवाद और सहयोग के माध्यम से संबंधों को मजबूत बनाए रखा है। नई राजनीतिक परिस्थितियों में भी यही उम्मीद की जा रही है कि दोनों देश आपसी सम्मान और साझेदारी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। नेपाल में हो रहा यह राजनीतिक परिवर्तन दक्षिण एशिया की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि नई नेतृत्व पीढ़ी भारत के साथ संबंधों को किस दिशा में ले जाती है।

नेपाल में उभर रही नई राजनीतिक ताकतें देश की राजनीति में ताजगी और बदलाव की उम्मीद लेकर आई हैं। बालेन शाह और उनकी पार्टी की सफलता इस बात का संकेत है कि जनता अब पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर नए विकल्पों को अपनाने के लिए तैयार है। हालांकि भारत-नेपाल संबंध इतने गहरे और बहुआयामी हैं कि किसी एक राजनीतिक परिवर्तन से उनमें अचानक बड़ा बदलाव आना कठिन है। संभव है कि नई सरकार अधिक आत्मनिर्भर और संतुलित विदेश नीति अपनाए, लेकिन सहयोग और पारस्परिक निर्भरता दोनों देशों को एक-दूसरे के करीब बनाए रखेगी। इसलिए नेपाल की राजनीति में चाहे जितना भी बदलाव आए, भारत और नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध आने वाले समय में भी दोनों देशों के रिश्तों की मजबूत नींव बने रहेंगे।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

देश में बच्चों के लापता होने का बढ़ता संकट...

मानव अंगों की तस्करी गिरोह के सक्रिय होने की आशंका

बच्चों के लापता होने के कारण केवल मानव तस्करी या अंग तस्करी तक सीमित नहीं माने जा सकते। इसके पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। कई किशोर और किशोरियाँ प्रेम प्रसंग, पारिवारिक तनाव या बेहतर जीवन की तलाश में घर छोड़ देते हैं। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण भी कई बच्चे काम की तलाश में घर से दूर चले जाते हैं।

भारत में बच्चों के लापता होने के मामले हाल के दिनों में एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक समस्या बन चुके हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच देशभर में कुल 33,577 बच्चे लापता दर्ज किए गए, जिनमें से 7,777 बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। यह आंकड़ा न केवल परिवारों के लिए पीड़ा का विषय है, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

सबसे प्रभावित राज्यों में पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से सामने आए हैं। सबसे अधिक मामलों की संख्या पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है, जहाँ 19,145 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 15,465 को ढूंढ लिया गया है, जबकि 3,680 अब भी लापता हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 4,256 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 1,059 बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, चंडीगढ़, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पांडिचेरी में भी बच्चों के लापता होने की रिपोर्टें सामने आई हैं। दिलचस्प बात यह है कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली में इस अवधि के दौरान एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बेहतर रिपोर्टिंग, कम जनसंख्या या प्रशासनिक अंतर के कारण हो सकता है।

आधिकारिक आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि कुछ राज्यों से अनपेक्षित रूप से कोई रिपोर्ट नहीं मिलना जिलों और राज्यों के रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग प्रणाली की विविधता को दर्शाता है। पिछले चार वर्षों में लगभग 36,000 बच्चे आज भी अनट्रेस्ड हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि यह समस्या केवल एक वर्ष का मामला नहीं, बल्कि लंबे समय से जारी है।

बच्चों के लापता होने के कारण केवल मानव तस्करी या अंग तस्करी तक सीमित नहीं माने जा सकते। इसके पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। कई किशोर और किशोरियाँ प्रेम प्रसंग, पारिवारिक तनाव या बेहतर जीवन की तलाश में घर छोड़ देते हैं। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण भी कई बच्चे काम की तलाश में घर से दूर चले जाते हैं। कुछ मामलों में बाल तस्करी और अवैध श्रम के लिए बच्चों को घरेलू काम या अन्य गतिविधियों में लगा दिया जाता है। इसके अलावा अपहरण और पारिवारिक विवादों के कारण भी बच्चों के लापता होने की घटनाएँ सामने आती हैं।

जहाँ प्रत्यक्ष रूप से अंग तस्करी के बड़े गिरोहों के सक्रिय होने का कोई व्यापक प्रमाण सामने नहीं आया है, वहीं कुछ स्थानों पर बाल तस्करी, शोषण और घरेलू काम के लिए बच्चों को अवैध रूप से ले जाने के मामले सामने आए हैं। कुछ घटनाओं में बच्चों को झूठी गोद लेने या घरेलू श्रम के लिए ले जाने की जानकारी भी मिली है, जिससे यह संकेत मिलता है कि तस्करी के कुछ नेटवर्क सक्रिय हो सकते हैं।

सरकार और पुलिस द्वारा बच्चों को खोजने के लिए 'खोया-पाया' पोर्टल जैसे माध्यमों के जरिए प्रयास किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी इस समस्या को गंभीर मानते हुए केंद्रीय और राज्य स्तर पर बेहतर समन्वय तथा प्रभावी ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

इसके बावजूद कई राज्यों में आंकड़ों की कमी, संसाधनों का अभाव और अंतर-राज्यीय समन्वय की कमी जैसी चुनौतियाँ प्रभावी कार्रवाई में बाधा बनती हैं। बच्चों का लापता होना केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी है। अभिभावकों की जागरूकता, समुदाय की सतर्कता और स्थानीय स्तर पर सहयोग अत्यंत आवश्यक है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा तंत्र और तकनीकी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना होगा। देश में हजारों बच्चों का लापता होना एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। यह भी स्पष्ट है कि हर मामला मानव तस्करी या अंग तस्करी से जुड़ा नहीं होता, बल्कि कई मामलों के पीछे सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कारण भी होते हैं।

प्रशासन अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, लेकिन बेहतर आंकड़ा संग्रह प्रणाली, पर्याप्त संसाधन, पुलिस और समाज के बीच समन्वय तथा सतर्कता के अभाव में यह समस्या बनी हुई है। अब आवश्यक है कि सरकार, पुलिस, नागरिक समाज और स्थानीय समुदाय मिलकर बच्चों की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त और ठोस रणनीति विकसित करें, जिससे इस गंभीर समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)